THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) All India Small Paper Mills Association have informed that a study undertaken on their behalf has estimated that the production of paper and paper board by the turn of the century would be around 27.7 lakh tonnes against a projected demand of 37.9 lakh tonnes. The shortfall in production has been attributed to the inadequate availability of wood based raw material and waste paper. Besides, rising costs of inputs viz. raw material, coal, power and chemicals may adversely affect profitability of paper mills resulting into lower production. The optional use of non-conventional raw material, agro residues and bagasse may also not be feasible due to problem of effluent control and their irregular availability.

(b) and (c) Government have taken various policy measures and provided following incentives to paper mills for sustained growth of the paper industry :

(i) Paper units using minimum 75% pulp derived from bagasse, agricultural residues and other non-conventional raw materials have been exempted from the provisions of compulsory licensing subject to clearance from the locational angle.

(ii) Paper units using minimum 75% agro-residues such as bagasse and jute are fully exempted from excise duty.

(iii) Paper mills using agro residues and other non-conventional raw materials atleast upto 50% are charged excise duty at concessional rates.

(iv) Import of wood pulp and waste paper is freely allowed under the EXIM policy at a low rate of customs duty without any need for obtaining import licence.

Central Pulp & Paper Research Institute (CPPRI), Saharanpur, an autonomous body under Government and a premier institution for R&D in paper technology has undertaken several projects to assist non-wood based pulp and paper industry. The Institute is also engaged in developing appropriate technology for chemical recovery plant for small pulp mills using non woody raw material.

उत्तर प्रदेश में नए उद्योग

1695. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए चालू वर्ष और अगले वर्ष में इस राज्य में कितने उद्योग स्थापित किए जाने की योजना है,

(ख) उक्त उद्योगों को कितने जिलों में स्थापित किए जाने की संभावना है, और

(ग) उक्त उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णासाही) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में संयुक्त, सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र में लगभग 33,000 उद्योग लगाने की योजना है। ये उद्योग उक्त राज्य के प्रायः सभी जिलों में लगाये जाने हैं। इसमें लगभग 2.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेशी निवेश

1696. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई आर्थिक-नीति के परिणाम स्वरूप देश में होने वाले विदेशी पूंजी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार को आज तक कितने देशों से पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी शर्तें क्या-क्या हैं, और

(ग) किन-किन देशों ने पूंजी निवेश की अनुमति दे दी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):

(क) जी, हां । अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 1992 के अन्त तक नीति के बाद के 15 महीनों में विदेशी सहयोग स्वीकृतियों में भारत में कुल 3679.63 करोड़ रु० के विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है जबकि नीति से पहले के 15 महीनों अर्थात् मई, 1990 से जुलाई, 1991 में अनुमोदित निवेश कुल 192.74 करोड़ रु० था ।

(ख) और (ग) : 52 देशों की कम्पनियों द्वारा 3679.63 करोड़ रु० के प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना वाले 740 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं । विदेशी पूंजी निवेश की ये स्वीकृतियां नई औद्योगिक नीति के अनुरूप हैं । देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1. फ्रांस	27. नार्वे
2. जर्मनी	28. पुर्तगाल
3. इटली	29. पोलैंड
4. जापान	30. कतार
5. कोरिया (दक्षिण)	31. सिंगापुर
6. स्विटजरलैंड	32. स्पेन
7. यू० के०	33. स्वीडन
8. यू० एस० ए०	34. थाईलैंड
9. आस्ट्रेलिया	35. रूस
10. आस्ट्रिया	36. यू० ए० ई०
11. बहरीन	37. उकरीन
12. बेल्जियम	38. उरुग्वे
13. ब्राजील	39. मेक्सिको
14. बरमुडा	40. वर्जिन द्वीपसमूह
15. कनाडा	41. बुल्गारिया
16. चीन	42. ब्रिटिश वर्जिनिया
17. चेकोस्लाविया	43. करोटिया
18. डेनमार्क	44. इजरायल
19. लतविया	45. कुवैत
20. फिनलैंड	46. माल्टा
21. हांगकांग	47. पनामा
22. इन्डोनेशिया	48. फिलिपाइन्स
23. कोरिया (उत्तर)	49. सऊदी अरबिया
24. मलेशिया	50. दक्षिण अफ्रीका
25. नीदरलैंड	51. थाईलैंड
26. न्यूजीलैंड	52. युगोस्लाविया